eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

पर्यावरण प्रदूषण, धारणीय विकास एवं कॉप–27

[1]**श्री विकास**
[1]सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, डॉ0 अंबेडकर गवर्नमेंट पी0 जी0 कॉलेज ऊंचाहार, रायबरेली (उ0प्र0)

Received: 20 Jan 2023, Accepted: 28 Jan 2023, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2023

Abstract

हम पृथ्वी पर तरह तरह के परिवेश में रहते हैं। यह परिवेश ही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है जिसका मानव जीवन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण जीवों के विभिन्न रूपों के अस्तित्व और वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है जिसमें मनुष्य भी शामिल है। जीवित प्राणी जैविक पर्यावरण बनाते हैं। भौतिक और जैविक पर्यावरण परस्पर क्रिया करके चिर स्थायी तंत्र का निर्माण करते हैं।

मुख्य शब्द– पर्यावरण संरक्षण, धारणीय विकास, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC), कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज (COP).

Introduction

प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहता था लेकिन जैसे–जैसे वह विकसित होता गया वैसे–वैसे एक नए तरह का पर्यावरण विकसित करता गया। यही मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है जिसके कारण पर्यावरण परिवेश का तेजी से पतन हो रहा है। इससे भविष्य में उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जल संसाधन भण्डार कम हो रहे हैं। इसलिए औद्योगिक विकास के किसी भी व्यापक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना जरूरी है। इस संदर्भ में अब अर्थशास्त्री 'धारणीय विकास' की बात करते हैं। इस संदर्भ में UNFCCC - United Nations Framework Convenstion on Climate Change के तत्वाधान में COP - Conference of Parties सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

उद्देश्य–

1. पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडलीय परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना–

1. पर्यावरण प्रदूषण ने जल, वायु, भूमि, आदि की गुणवत्ता में हास किया है।
2. पर्यावरण प्रदूषण ने वायुमंडलीय परिवर्तन किया है जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने विभिन्न प्रकाशित लेखों, विभिन्न समितियों के सुझाव, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं और समाचार पत्रों तथा विषय से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

प्रस्तावना– मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप (विशेष रूप से औद्योगिकीकरण के तेज प्रगति के कारण) विश्व भर में पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। अधिकतर क्षति स्थायी है तथा उसकी भरपाई संभव नहीं है। औद्योगिकीकरण से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक विनाश हुआ है। 1972 में प्रकाशित अपनी पुस्तक The Limits to Growth में डी एच मीडौस, डी एल मीडौस और आर रेंडर्स ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बहुत से संसाधन अनवीनीकरणीय है तथा उनके मौजूदा उपयोग की दर इतनी ज्यादा है कि कुछ वर्षों या कुछ दशकों के बाद हो सकता है कि वे समाप्त हो जायें बाद में किए गए बहुत सारे अन्य अध्ययनों में भी पर्यावरण की क्षति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसलिए अब पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाने लगा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट–1992 के अनुसार पर्यावरण समस्यायें दो तरह से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकती हैं–

1. पर्यावरण की गुणवत्ता।
2. पर्यावरण को होने वाली क्षति का भविष्य में उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पर्यावरण क्षति का अध्ययन निम्नलिखित वर्गों के आधार पर किया जा सकता है–

जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस व खतरनाक अपशिष्ट, भूमि का क्षरण, वनों का विनाश, जैवविविधता का नाश तथा वायुमंडलीय परिवर्तन।

जल प्रदूषण– जल का सर्वाधिक प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक व खनन गतिविधियों का तेज विकास होता है उन क्षेत्रों में उद्योगों के अपशिष्ट नदियों में बहाए जाते हैं जिससे नदियों जल प्रदूषित हो जाता है। इन प्रदूषकों को पीने के पानी से अलग करना कठिन हो जाता है। न केवल शहरों व कस्बों के आसपास प्राप्त होने वाला सतही जल धीरे–धीरे और प्रदूषित होता चला गया है बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित होता जा रहा है क्योंकि भूमि में खतरनाक रसायन व अन्य हानिकारक पदार्थ रिस–रिस कर नीचे पानी में मिल रहे हैं।

जल प्रदूषण विकासशील देशों के लिए सबसे गंभीर पर्यावरण समस्या है। प्रदूषित जल पीने से तरह–तरह की बीमारियां फैलती है जिनका सबसे बुरा प्रभाव बच्चों तथा गरीब जनता पर पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है और करोड़ों लोग जल प्रदूषण जनित बीमारियों का शिकार होते हैं।

वायु प्रदूषण– वायु प्रदूषण मुख्य रूप से ऊर्जा उपयोग, वाहनों का उत्सर्जन तथा औद्योगिक उत्पादन आदि से पैदा होता है। जैसे–जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास जोर पकड़ेगा वायु प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। वातावरण में उड़ रही धूल, मिट्टी और धुआं से गंभीर श्वास संबंधी बीमारियों हो रही हैं। वाहनों के उत्सर्जन से निकलने वाला सीसा बच्चों के मानसिक क्षमताओं के विकास में बाधक है। अत्यधिक सीसे से वयस्क लोग उच्च रक्तचाप व हृदय रोग जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो देश अधिक सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करते हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। गरीब व मध्य आय वाले देशों में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सर्वाधिक है।

ठोस व खतरनाक अपशिष्ट– औद्योगिकरण से बहुत सारे शहरों में ठोस अपशिष्ट इतनी अधिक मात्रा में पैदा हो रहा है कि उसे एकत्रित करना और उससे निपट पाना मुश्किल हो रहा है। जहाँ कहीं

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

ठीक तरह से एकत्र हो भी रहा है वहाँ ठोस अपशिष्ट को सुरक्षित ढंग से निपटाना संभव नहीं है। कई बार तो इसे खुले इलाके में ढेर बना कर फेंक दिया जाता है जो समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ये जमा ठोस व अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य तथा उनकी उत्पादकता पर कुप्रभाव डालते हैं।

भूमि का क्षरण– मानवीय गतिविधियों के कारण धरती के हरित क्षेत्र में गिरावट हुई है जिससे भूमि का क्षरण बढ़ा है। भूक्षरण या भूमि कटाव के कारण भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह बह जाती है जिससे कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि कटाव के कारण मिट्टी बहकर बांधों में, जलाशयों में तथा सिंचाई के लिए तैयार की गयी नहरों में जम जाती है। इससे सिंचाई व्यवस्था पर, जल के माध्यम से आवागमन पर तथा जल में रहने वाले जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

वनों का विनाश– वन वनों में रहने वाले लोगों के जीवन का साधन तो है ही साथ ही वे बहुत प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन भूमि का संरक्षण करते हैं और उसकी उत्पादकता बढ़ाते हैं। मौसमी चक्र को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। वाष्पीकरण के जरिये स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन कार्बन को नियंत्रित करके भूमंडलीय जलवायु को सुरक्षित व स्थिर बनाते हैं। इस प्रकार वन पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण में संतुलन बनाने में सहायक होते हैं तथा जैविक विविधता एवं प्राकृतिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने में योगदान देते हैं। इन फायदों के बाद भी मानव द्वारा वनों का विनाश लगातार जारी है।

जैव विविधता की हानि– जैव विविधता मानव को भौतिक संपदा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए के लिए आगत उपलब्ध कराता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जीव जंतुओं की ऐसी कई जातियों व प्रजातियों का जिक्र है जो अब लुप्त प्राय हो गई है। इनके लुप्त होने का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां है। उष्णकटिबंधीय वन जीव–जंतुओं की विभिन्न जातियों व प्रजातियों के मुख्य निवास स्थान होते हैं तथा इन वनों में ही इनका अधिक संकेंद्रण होता है। परंतु उष्णकटिबंधीय वनों का ही मनुष्यों ने ज्यादा सफाया किया है। इसी प्रकार समुद्र तटीय तथा ताजा जल स्रोतों में रहने वाले जीव जंतुओं व प्रवाल –भित्ति का भी बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है।

वायुमंडलीय परिवर्तन– तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऐसे वायुमंडलीय परिवर्तन तेजी के साथ हो रहे हैं जो भावी पीढ़ियों के लिए अनेक अनिश्चित व स्थायी दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं । इन दुष्प्रभावों की पूरी जानकारी अभी नहीं हो पाई लेकिन हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने इनमें से दो खतरो (ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ओजोन परत का हास) की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय संरचना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ गैसे तथा वायुधुंध आने वाले सौर विकिरण तथा जाने वाले इंफ्रारेड विकिरण को प्रभावित करते हैं। पानी के वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ओजोन वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसे इंफ्रारेड ऊर्जा के अंतरिक्ष में होने वाले प्रवाह को बाधित करके भूमि की सतह को गर्म करती हैं। इन गैसों के प्राकृतिक स्तरो द्वारा सृजित गर्म प्रवाह प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव भूमि को उस स्तर तक गर्म रखता है जिससे जीवन संभव बनता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरुप उत्सर्जित गैसों से यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

औद्योगिक गतिविधियों, फॉसिल ईंधन के ज्वलन के फलस्वरूप, खेती व भूमि के उपयोग के परिवर्तनों के परिणामस्वरुप ताप को रोक कर रखने वाली अन्य गैसों का संकेंद्रण भी बढ़ गया है जिससे वैश्विक गर्मी के बढ़ जाने का खतरा बढ़ गया है। इस कारण बर्फ की चट्टानों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में तेज वृद्धि हो सकती है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ आ सकती है। तेज गर्मी के चलते कई संक्रामक रोगों में वृद्धि हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार मानव समाज व प्राकृतिक वायुमंडल 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वैश्विक गर्मी का सामना करने की क्षमता नहीं रखता है। यदि वैश्विक गर्मी का स्तर इससे अधिक हो गया तो पर्यावरण के लिए तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप ओजोन परत का क्षरण भी हो रहा है। CFCs मानव द्वारा निर्मित औद्योगिक रसायन है जो ना तो वर्षा में घुलते हैं और ना ही वायुमंडल की अन्य गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। CFCs द्वारा जो क्लोरीन वायुमंडल में छोड़ी जाती है उसके परिणामस्वरूप ओजोन परत का हास होता है। ओजोन परत का हास होने पर पृथ्वी के धरातल पर सौर अल्ट्रावायलेट विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है जो प्राकृतिक संपदा के विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। यह किरणें मानव में अनेक त्वचा संबंधी रोगों को उत्पन्न कर सकती हैं।

पर्यावरण संरक्षण तथा धारणीय विकास– औद्योगिक विकास के किसी भी व्यापक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना जरूरी है। इस संदर्भ में अब अर्थशास्त्री धारणीय विकास की बात करते हैं। धारणीय विकास का उल्लेख पहली बार 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा विश्व संरक्षण युक्ति प्रस्तुत करते समय किया गया। 1987 में बरन्टलैंड रिपोर्ट Our Common Future में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान में लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को इस प्रकार पूरा करना कि आगे वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य पर कोई आंच ना आयें।

धारणीय विकास केवल तभी संभव है यदि पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी विकास पथ तभी धारणीय है यदि कुल पूंजी परिसंपत्ति या स्थिर रहती है या फिर उसमें वृद्धि होती है। धारणीय विकास के पीछे सीधा सा तर्क यह है कि किसी भी देश का संसाधन आधार तथा उसके जल, वायु तथा भूमि के स्रोत उस देश की सभी पीढ़ियों वर्तमान तथा भावी के संयुक्त धरोहर है। अल्पकालीन लाभों के लिए इस धरोहर का विनाश करने का अर्थ है भावी पीढ़ियों के हितों का हनन करना। इसलिए यह अनुचित है। इसलिए सरकार को अपनी नीति निर्धारण में पर्यावरण लेखांकन की व्यवस्था करनी चाहिए। नीति निर्धारक यह लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि पर्यावरण परिसंपत्तियों का कोई निवल हास नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई पर्यावरण संसाधन एक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होता है अथवा उसका हास होता है तो किसी अन्य क्षेत्र में उसके बराबर या उससे अधिक मूल्य के संसाधन पैदा किया जायेगा।

Humman Development Report 1996 में धारणीय आर्थिक विकास की जगह धारणीय मानव विकास की बात की है। धारणीय मानव विकास का अर्थ यह है कि भावी पीढ़ियों को मानव कल्याण की कम से कम इतनी क्षमता तो दी ही जायें जो कि मौजूदा पीढ़ी को उपलब्ध है। इसके लिए मौद्रिक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

लेखांकन से बहुत आगे जाकर ऐसे गैर मौद्रिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि सभी लोग एक सुखमय व् सन्तुष्ट जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास– तीव्र औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के कारण वैश्विक गर्मी और ओजोन परत का हास बढ़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मई 1988 में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए ताकि पर्यावरण संरक्षण के संबंधों में कोई सामान्य नीति तैयार की जा सके। यह बदलते हुए पर्यावरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था।

जून 1992 में ब्राजील के शहर में पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) में 132 देशों के राज्य अध्यक्षों ने एक समझौते को मूर्तरूप दिया जिसे Framework Convention on Climate Change नाम दिया गया। इस समझौते पर 160 देशों ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते ने एक पथ प्रशस्त किया ताकि बढ़ते जलवायु खतरो के लिए कोई सामान्य हल निकाल सकें। 1994 में जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल (Inter & Governmental Panel on Climate Change) ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि कोयला व तेल को जलाने से जो उत्सर्जन पैदा हो रहा है वह सौर्य–गर्मी को वायुमंडल में सामान्य से अधिक रोक रहा है। वातावरण में हो रहे इन गंभीर परिवर्तनों से धरती के तापमान में तेज वृद्धि हो सकती है तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तथा सूखे की समस्या पैदा हो सकती है।

दिसंबर 1997 में जापान के शहर क्योटो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लक्ष्यों तथा समय–सारणी तैयार की जा सके UNFCCC -United Nations Framework Convention on Climate Change के द्वारा आयोजित इस बातचीत में समझौते तक पहुंचने में 5 वर्षों की अवधि लगी। समझौते को लागू करने के लिए उपयुक्त संख्या में देशों की स्वीकृति मिलने में 8 वर्ष लग गए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते के प्रति कोई वचनबद्धता स्वीकार नहीं की।

क्यूटो विज्ञप्ति में औद्योगिक देशों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वह 2012 तक अपने उत्सर्जन को 1990 में उत्सर्जन स्तर से 5% तक कम करें तथा विकासशील देशों की इस बारे में सहायता करें कि ये देश जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बच सके। समय–समय पर UNFCCC द्वारा अनेक कान्फ्रेंस किए गये लेकिन विकसित देशों द्वारा कोई उचित सहयोग नहीं प्राप्त हुआ।

COP–27– यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) में शामिल राष्ट्रों का 27वाँ सम्मेलन (Conference of the Parties COP-27) मिस्र में शर्म–अल–शेख में 20 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शुक्री की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 92 देशों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त लगभग 35000 प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने भागीदारी दर्ज की। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले वर्ष नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP–26 में की गई प्रतिबद्धताओं की दिशा में विचार विमर्श के अतिरिक्त पर्यावरण सुधार के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए प्रतिबद्ध राशि की दिशा के चर्चा इस सम्मेलन में मुद्दों में शामिल थी। कोपनहेगन में 2015 में हुए COP–15 में इसके

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

लिए 100 अरब डॉलर की निधि बनाने का निर्णय लिया गया था तथा 2020 से यह राशि विकासशील देशों को प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जानी थी कि विकसित देश ऐसा करने में विफल रहे । विकासशील देशों द्वारा यह मुद्दा प्रतिवर्ष COP सम्मेलन में उठाया जाता रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए क्लाइमेट फंडिंग का मुद्दा कॉप–27 भी प्रमुख रहा। इस दिशा में सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रगति 'नुकसान व क्षति कोष' (Loss and Damage Fund) के गठन के लिए विकसित देशों की सहमति रही। इस सहमति के लिए ही सम्मेलन को दो दिन आगे बढ़ाना पड़ा । नुकसान व क्षति कोष के तहत धनी देश जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं से भविष्य में निर्धन देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सहमत हुए है।

Loss and Damage Fund के स्वरूप पर कोई निर्णय COP–27 में नहीं हो सका है। यह भी तय नहीं हुआ कि इस फंड में कौन सा धनी देश कितना योगदान करेगा है। इन मुद्दों को अगले सम्मेलन के लिए टाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पार्टियों का आगामी सम्मेलन COP–28 संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में होगा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव– COP–26 की तरह ही COP–27 में भी अमीर देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले खतरों का सामना करने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। COP–27 में नुकसान व क्षति कोष (Loss and Damage Fund) के गठन की सहमति विकसित देशों द्वारा दी गयी लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया कि धनी देशों का इस फंड में कितना योगदान होगा। इन मुद्दों को अगले सम्मेलन के लिए टाल दिया गया।

रूस–यूक्रेन संकट ने यूरोप की ऊर्जा नीति को प्रभावित किया है इसलिए ऊर्जा संकट से निपटने के लिए विकसित देश ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत के लिए पेट्रोलियम और गैस उत्पादन पर फिर से जोर देने लगे हैं। हमें इस बात को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि भले ही यूरोप स्वच्छ ऊर्जा नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखता है लेकिन ऐसा होते हुए भी प्रदूषित स्रोतों वाले ऊर्जा उत्पादन में फिर से निवेश किया जा रहा है और यह जलवायु के लिए बुरा है।

उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को महंगी स्वच्छ ऊर्जा वाले स्रोतों को अपनाने के लिए कैसे कहा जा सकता है जो अब भी ऊर्जा में कमी जैसे दौर से गुजर रहे हैं। विकसित देशों की निर्भरता अभी भी जीवाश्म ईंधन पर ही हैं जिसमें कोयला संयंत्रों और खदानों की फिर से शुरुआत करना शामिल है। पिछले साल तक वैश्विक समुदाय कोरोना टीके के सहयोग करने और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बात कर रहा था लेकिन बाद में आरोप–प्रत्यारोप के दौर चले। यह युद्ध का समय नहीं है और ना ही यह हमारे मूल्यों पर आधारित मतभेदों के लिए सही वक्त है। हमें एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की आवश्यकता है जो सभी देशों की मानवता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साथ ले आए ताकि हम इस बात पर विचार कर सकें कि किस तरह हम आने वाले अस्तित्व के संकट को रोंके और कैसे एक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। ऐसा केवल तभी संभव है जब हम वैश्विक शासन की एक नियम आधारित प्रणाली पर वापस जायें जो एक अमीर और ताकतवर लोगों के लिए भी नियम निर्धारित करें ना कि केवल गरीबों को ही

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

इसका पालन करने के लिए कहे। जलवायु परिवर्तन के मामलों में प्रदूषण फैलाने वाले को यह सब कुछ करना होगा जिस पर सबकी सहमति बनेगी।

पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के लिए हमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को क्रमबद्ध तरीके से सही नीति द्वारा समाप्त करना होगा। विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। इसके लिए वित्तीय प्रणालियों को भी पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि अलग तरीके से विकास करने के लिए धन उपलब्ध हो सके। हम जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे विकासशील देशों पर संसाधन स्वयं जुटाने का भार नहीं डाल सकते हैं।

सन्दर्भः–

1. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, आर्थिक संवर्धन एवं विकास के मुद्दे –चैप्टर 9 (एस एन सिंह –अग्रवाल पब्लिकेशन 2014–15)।
2. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विजन एंड चैलेंज चैप्टर–18, चैप्टर–39 (डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, एम. बी. पब्लिकेशन 2022)।
3. आर्थिक समीक्षा 2021–22, चैप्टर–6 (भारत सरकार; वित्त मंत्रालय–आर्थिक कार्य विभाग)।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर–3 (वी. के. पूरी, एस. के मिश्र, भारत गर्ग–हिमालय पब्लिशिंग हाउस 2022 संस्करण)।
5. अमर उजाला 20 नवंबर 2022।
6. प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023।